(iii) to increase biomass availability, especially, fuelwood and fodder; ! and

(iv) restoration of ecological balance.

Tree planting • afforestation over an area of 10,640 million hectare was achieved against the target of 10,256 million hectare and 265.50 crore seedlings have been distributed against the target of 400.00 crore seedlings upto 1991-92.

(b) There are differing estimates of wastelands. The National Wastelands Development Board has estimated the ana of Wastelands at 120 mha whereas the estimate of the Society for Promotion of Wastelands Development is 130 mha.

(c) No targets for land conversion have yet been envisaged by the reconstituted National Wastelands Development Board for the Eighth Five Year Plan.

Financial Assistance for construction of Houses in A. P.

732. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to provide financial assistance to the tune of Rs. 22.5 crores to Andhra Pradesh for construction of houses in the rural areas; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY) :

(a) and (b) A request for the sanction of Rs. 22.50 crores as Government of India subsidy for a rural housing programme in Andhra Pradesh during 1992-93 has been received from the State Government. They have proposed to take up 1.80 lakh houses for the weaker Sections, with 1.45 lakh houses in rural areas and 0.35 lakh homes in urban areas. The total project outlay for 1.45 lakh houses in the rural areas has been mentioned as Rs. 112.52 crores. The State Government has requested the Government of India to provide 20% of the total outlay amounting to Rs. 22.50 crores as subsidy during 1993-93.

गुजरात में कम लागत पर सफाई व्यवस्था

733. श्री राम सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में कम कीमत पर सफाई व्यवस्था के लिये कुछ शहरों का पता लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं, और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

गुजरात में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च किया गया धन

734. श्री राम सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान गुजरात में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च किए जाने वाले प्रस्तावित धन की राशि कितनी है;

(ख) उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने विगत वर्ष के दौरान उसे आवंटित की गई पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया था, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) 1992-93 के दौरान गुजरात राज्य में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	1992-93 के दौरान आवंट
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.1
2. जवाहर रोजगार योजना	78.9
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	16.3

(ख) 1992-93 के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1991-92 के दौरान स्वास्थ्य के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए 5.79 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी। वर्ष 1991-92 के दौरान साक्षरता अभियान (लाइटेन्स लर्निंग बोर्ड) पर अनुमानित खर्च 6.20 करोड़ रुपये था।

(ग) व (घ) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य को आबंटित धनराशि के इस्तेमाल की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

(करोड़ रुपयों में)

कार्यक्रम	आबंटन	उपयोग
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	21.32	23.08
2. जवाहर रोजगार योजना	81.89	100.39
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	16.33	15.14

इस प्रकार, 191-92 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम को छोड़कर प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निधियों का उपयोग आबंटित राशि से अधिक हुआ है।

ग्रामीण उद्योग के लिए अपर्याप्त धनराशि

735. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए बजट वर्ष में अपर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1992-93 के दौरान इस विभाग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जरिए योजनागत स्कीमों के तहत ग्रामीण उद्योगों के लिए 19100 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। 1991-92 के दौरान बजट में इतना ही प्रावधान किया गया था। तथापि, पुनर्विनियोग द्वारा 1991-92 के दौरान बजट में 200 लाख रु. की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामोद्योग के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को आबंटित की गयी राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (रु. लाखों में)
1989-90	17500
1990-91	18600
1991-92	19300

उत्तर प्रदेश को भूमि सुधारों के लिये विशेष सहायता

736. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश को भूमि सुधारों के लिए विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?